के अन्तर्गत आने आले आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यक प्रयोयजनों के लिए निर्माण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो आवासीय स्थलों के वाणिज्यक स्थलों में रूपान्तरण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक निर्माण कार्यों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से सर्वे किया जाता है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में निर्धारित पद्धति के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

गत चार वर्षों के दौरान चलाये गए मुकदमों की संख्या निम्नलिखित है :—

1990–91	5
1991–92	19
1992–93	304
1993–94	481

राज्य सरकारों के स्वास्थ्य प्रस्तावों को मंजूरी

1717. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
श्री ईश दत्त यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों, विशेषत: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से भूमिगत मल व्ययन योजनाओं के संबंध में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन योजनाओं को मंजूरी दे दी है ; और

(घ) अस्वीकृत की गई योजनाओं के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, नहीं। तथापि, हुडको को गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के एक प्रस्ताव सहित 8 प्रस्ताव मिले हैं।

(ख) राज्य-वार ब्यौरे विवरण में दिए अनुसार हैं **(नीचे देखिये)**।

(ग) हुडको द्वारा 3 स्कीमें स्वीकृत की जा चुकी हैं और 5 स्कीमें प्रक्रियाधीन हैं।

(घ) 5 स्कीमों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(i) गुजरात राज्य में बड़ौदा के लिए मलजन लोधन संयंत्र का संवर्धन।

संशोधित प्रस्ताव, बड़ौदा नगर निगम द्वारा अभी भी भेजा जाना है।

(ii) जामनगर के लिए भूमिगत सीवरेज स्कीम।

संशोधित स्कीम मार्च, 1994 में ही मिली है और मूल्यांकनाधीन है।

(iii) सूरत में मलजन शोधन संयंत्र का निर्माण।

इस परियोजना के लिए स्कीम मार्च, 94 में ही हुडको को प्राप्त हुई है और मूल्यांकनाधीन है।

(iv) महाराष्ट्र में लोनावाला कस्बे के लिए भूमिगत सीवरेज स्कीम।

यह स्कीम हुडको के विचाराधीन है।

(v) उत्तर प्रदेश में शताब्दी नगर चरण VI में, मेरठ में बाह्य सीवरेज स्कीम।

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अभी भी विभिन्न संगठनात्मक तकनीकी और वित्तीय स्पष्टीकरण हुडको के विचारार्थ भेजे जाने हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों में हुडको द्वारा प्राप्त सीवरेज निपटान स्कीमों की सूची

क्रमांक	राज्य का नाम	स्कीम का नाम	योजना लागत अभ्युक्ति (रु० लाखों में)
1	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम में विस्तृत सीवरेज स्कीम चरण–II, उप चरण–I	1668.19
2	गुजरात	पश्चिम ए यू डी ए सीवरेज परियोजना	8900.00
3	कर्नाटक	बंगलौर में के० एंड सी० घाटी में 50 एम एल डी तृतीय शोधन संयंत्र	1739.21
4	गुजरात	बड़ौदा के लिये सीवरेज शोधन संयंत्र का संवर्द्धन	1000.00
5	गुजरात	जामनगर के लिये भूमिगत सीवरेज स्कीम	4153.00
6	गुजरात	सूरत में सीवरेज शोधन संयंत्रों का निर्माण	2528.04
7	महाराष्ट्र	लोनावाला नगर के लिये भूमिगत सीवरेज स्कीम	216.10
8	उत्तर प्रदेश	शताब्दी नगर, चरण–I मेरठ में बाह्य सीवरेज स्कीम	469.70

Delhi Rent Control (Amendment) Bill

1718. SHRI PRAMOD MAHAJAN:
SHRI VIREN J. SHAH:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 6177 given in Rajya Sabha on May 6, 1994 and state:

(a) whether Government have finalised the Delhi Rent Control (Amendment) Bill;

(b) if so, what are the details of amendments proposed to be made;

(c) what are the reasons for the delay in bringing a suitable legislation befort Parliament; and

(d) by when it is likely to be introduced in Parliament?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (d) The Delhi Rent Bill is under finalisation and will be introduced in the Parliament shortly.

Construction of Quarters by DDA

1719. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the total number of different types of quarters (category wise) constructed by the DDA during the last three years; year-wise;

(b) how many of these quarters (category-wise) were allotted to the persons registered with the DDA during the last three years, year-wise;